

वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

ANNUAL REPORT 2025-26



वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो
FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS BUREAU

विषयवस्तु

वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो का गठन	3
संक्षिप्त विवरण	5
स्थापना और प्रकार्य	7
नियुक्तियों हेतु संस्तुतियां	9
कौशल संवर्धन और सशक्तिकरण	12
• निदेशकों हेतु परिवर्धन कार्यक्रम	12
• लीडरशिप परिवर्धन कार्यक्रम	14
डाटाबेस, आईटी सिस्टम और प्रशासन	16
प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा	21
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	23

संक्षेपाक्षरों की सूची

एसीसी	मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति	आईओबी	इंडियन ओवरसीज बैंक
एआईसीआईएल	भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड	इरडाई	भारतीय बीमा विनियमन और परिवर्धन प्राधिकरण
बीओबी	बैंक ऑफ बड़ौदा	एलडीपी	लीडरशिप परिवर्धन कार्यक्रम
बीओआई	बैंक ऑफ इंडिया	एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
बीओएम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	एमडी	प्रबंध निदेशक
सीबीआई	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	एमडी तथा सीईओ	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण परिवर्धन बैंक
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक	नैबफिड	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और परिवर्धन बैंक
सीआईसी	केन्द्रीय सूचना आयोग	एनईसी	गैर- कार्यपालक अध्यक्ष
सीएमडी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
डीडीपी	निदेशकों हेतु परिवर्धन कार्यक्रम	एनआईसीएल	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग	ओबीसी	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
डीजीएम	उप महाप्रबंधक	ओआईसीएल	ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
डीएमडी	उप प्रबंध निदेशक	पी एन्ड एस बैंक	पंजाब एन्ड सिन्ध बैंक
डीपीई	लोक उद्यम विभाग	पीएनबी	पंजाब नेशनल बैंक
ईडी	कार्यपालक निदेशक	पीएसआईसी	सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनी
एफआई	वित्तीय संस्थान	पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
एफएसआईबी	वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो	आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
जीआईसी-आरई	जनरल इन्श्योरेन्स कापोरेशन ऑफ इंडिया	आरटीआई	सूचना का अधिकार
जीएम	महाप्रबंधक	एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
जीएमडी	महाप्रबंधक तथा निदेशक	सिडबी	भारतीय लघु उद्योग परिवर्धन बैंक
आईबीए	भारतीय बैंक संघ	यूबीआई	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आईआईएफसीएल	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड	डबल्यूटीडी	पूर्णकालिक निदेशक
आईएफसीआई	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	डबल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एफएसआईबी का गठन

श्री एम. नागराजु	श्री भानु प्रताप शर्मा	श्री के. मोसेस चालाई
सचिव, डीएफएस पदेन सदस्य (पीसबी/एफआई/पीएसआईसी)	अध्यक्ष	सचिव, डीपीई ^ पदेन सदस्य (पीसबी/एफआई/पीएसआईसी)
श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू	श्री अजय सेठ	
उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक @ पदेन सदस्य (पीसबी/एफआई)	अध्यक्ष, इरडाई * पदेन सदस्य (पीएसआईसी)	
श्री अनिमेष चौहान	श्रीमती उषा सांगवान	
पूर्व एमडी और सीईओ, ओबीसी विशेषज्ञ सदस्य (पीसबी/एफआई)	पूर्व एमडी, एलआईसी विशेषज्ञ सदस्य (पीएसआईसी)	
श्री शैलेन्द्र भंडारी	श्री ए. वी. गिरिजा कुमार	
पूर्व एमडी और सीईओ, आईएनजी वैश्य बैंक विशेषज्ञ सदस्य (पीसबी/एफआई)	पूर्व सीएमडी, ओआईसीएल विशेषज्ञ सदस्य (पीएसआईसी)	
श्री दीपक सिंघल	श्री सुजय बनर्जी	
पूर्व कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक विशेषज्ञ सदस्य (पीसबी/एफआई)	पूर्व पूर्णकालिक सदस्य, इरडाई विशेषज्ञ सदस्य (पीएसआईसी)	

^ 22 अप्रैल 2025 से

@ 09 अक्टूबर 2025 से

* 01 सितम्बर 2025 से

एफएसआईबी के अध्यक्ष और पार्ट-टाइम सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 2026 को समाप्त हो गया।

सचिवालय के प्रमुख अधिकारी

श्री शिशिर कुमार मिश्र (31 जुलाई 2026 तक)
श्री आशीष कुमार वर्मा (01 अगस्त 2026 से)

सचिव और महाप्रबंधक

सुश्री प्रदीप कौर गरेवाल

सहायक महाप्रबंधक

श्री गर्जेथिरा शिवा एस #

सहायक महाप्रबंधक

श्री प्रतीक जैन

प्रबंधक

श्री नवनीत मेहरोल

प्रबंधक

श्री देवांश रावत \$
श्री के वी साई कृष्णा &

सहायक प्रबंधक

श्री आदित्य एम.

सहायक प्रबंधक

उक्त सभी अधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक से हैं।

#20 अप्रैल 2026 से \$02 अप्रैल 2026 तक &04 मई 2026 से

संक्षिप्त विवरण

वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो (यह ब्यूरो) भारत सरकार का एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका कार्य है सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तियों, कार्यकाल के विस्तार और कार्यकाल के समापन हेतु संस्तुतियां करने के लिए समुचित पद्धतियों का परिवर्धन और कार्यान्वयन करना। इस ब्यूरो को अधिदेश दिया गया है कि निर्दिष्ट संस्थानों में बोर्ड / वरिष्ठ प्रबंधनतंत्र के स्तर पर अपेक्षित संरचना, कार्यनिष्पादन समाकलन प्रणालियों और प्रबंधकीय कार्मिकों हेतु आचरण और नैतिकता संहिता के निरूपण तथा प्रवर्तन के बारे में सरकार को परामर्श प्रदान करे।

नियुक्तियों के लिए संस्तुतियां

वर्ष 2025-26 के दौरान इस ब्यूरो द्वारा 20 अवसरों पर बैठक की और सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में 27 पदों के लिए 196 अभ्यर्थियों से वार्तालाप करते हुए संस्तुतियां की गईं। इस वर्ष के दौरान की गई 27 संस्तुतियों में से 13 संस्तुतियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, चार संस्तुतियां वित्तीय संस्थानों के लिए और 10 संस्तुतियां सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में विभिन्न पदों के लिए की गईं।

नियुक्तियों के लिए संस्तुतियां करने के अलावा इस ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान आईआईएफसीएल के एमडी, एक्जिम बैंक के डीएमडी, और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों के लिए भी संस्तुतियां की गईं।

इस ब्यूरो की बैठकों और अंतःक्रियाओं को ऑनलाइन के साथ-साथ भौतिक अर्थात् दोनों ही रूपों में आयोजित किए जाते हैं। सिसको वेबएक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बैठकों का आयोजन किया गया और वास्तविक बैठकों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।

कौशल संवर्धन और सशक्तीकरण

इस ब्यूरो को अन्य बातों के अलावा यह अधिदेश भी दिया गया है कि विनिर्दिष्ट संस्थानों में प्रबंधनतंत्र के कार्मिकों हेतु उचित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का निर्धारण करे। इस ब्यूरो ने बाहरी ज्ञानवान साझेदारों के सहयोग से दो कार्यक्रम तैयार किए हैं, जिनके नाम हैं – निदेशकों के परिवर्धन हेतु कार्यक्रम (डीडीपी) और लीडरशिप परिवर्धन कार्यक्रम (एलडीपी)।

डीडीपी का डिजाइन सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बोर्डों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। मई 2025 में पूर्ण हुए डीडीपी के तृतीय बैच का आयोजन हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग के साथ मिलकर मैसर्स इगॉन जीहेन्डर ने किया, जिसमें विभिन्न पीएसबी, एफआई और पीएसआईसी के 53 निदेशक शामिल हुए। सहभागियों में पूर्णकालिक निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारी निदेशक और नामित निदेशक शामिल हुए।

एलडीपी का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के उच्च-संभावना वाले कार्यपालकों को भावी लीडरों में रूपांतरित किया जाए। एलडीपी के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम बैचों हेतु कार्यक्रमों के लिए मैसर्स मैकेन्जी विज्ञ साझेदार के रूप में रहे। दिसम्बर 2025 में सम्पूर्ण हुए एलडीपी के षष्ठम बैच को 'आरोहण 2025 का नाम

दिया गया, जिसमें 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों के कुल 78 मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक सहभागी के रूप में रहे। सप्तम बैच से एलडीपी को आगे संचालित करने के लिए मैसर्स बीसीजी की साझेदारी में मैसर्स इगॉन जीहेन्डर का चयन विज्ञ साझेदार के रूप में किया गया है।



आरेख 1 – वर्ष 2025-26 में की गई संस्तुतियां

स्थापना और प्रकार्य

वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो (एफएसआईबी) की स्थापना भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं./14/1/2022-बीओ-आई दिनांक 1 जुलाई 2022 के अधीन की गई, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ अधिदेश प्राप्त संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की संस्तुति की जाए और इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कतिपय अन्य मामलों पर सलाह दी जाए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में पूर्णकालिक निदेशकों के सभी पदों हेतु इस ब्यूरो द्वारा चयन प्रक्रिया का संचालन एसीसी द्वारा अनुमोदित दिशानिदेशों के अनुसार की जाती है। इन दिशानिदेशों में पात्रता मानदंड (अर्थात आयु, अनुभव आदि), पद पर कार्यकाल, चयन पद्धति आदि शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, एसीसी ने अधिदेश प्राप्त संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु समेकित संशोधित दिशानिदेशों का अनुमोदन किया है। पात्रता मानदंडों में संशोधन के अलावा संशोधित दिशानिदेशों में किए गए परिवर्तनों में से कुछ प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं –

- कतिपय पूर्णकालिक निदेशकों के पदों यथा – भारतीय स्टेट बैंक में एमडी (एक पद), राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और सीईओ, बड़े बैंकों में ईडी (एक पद), भारतीय जीवन बीमा निगम में एमडी (एक पद) और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सीएमडी, जो पहले आंतरिक अभ्यर्थियों से भरे गए थे, अब ये निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु भी खुले हैं।
- एसबीआई में अध्यक्ष, एसबीआई में एमडी, बड़े बैंकों के अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एमडी और सीईओ, एलआईसी में सीईओ और एमडी, एलआईसी में एमडी और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सीएमडी के पदों हेतु एपीएआर अंकों पर विचार करने की पद्धति को हटा दिया गया है।
- सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में ईडी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में ईडी (केवल आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पद) के पदों के लिए एपीएआर अंकों के लिए भारिता को 50 प्रतिशत से कम कर के 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
- दंडात्मक नियम जोड़े गए हैं जिनके अनुसार, जिन उम्मीदवारों को पहले दो या उससे अधिक बार प्रमुख दंड मिल चुका है, उन्हें पूर्णकालिक निदेशकों के पदों के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

अधिदेशित संस्थान

सरकारी क्षेत्र के बैंक



वित्तीय संस्थान



सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां



नियुक्तियों हेतु संस्तुतियां

वर्ष के दौरान इस ब्यूरो द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों में 27 पदों के लिए संस्तुतियां की गईं। इस ब्यूरो द्वारा प्रति रिक्ति के लिए वार्तालाप किए गए अभ्यर्थियों का अनुपात 7.2 रहा, जो इन पदों के लिए अभ्यर्थियों के एक स्वस्थ पूल का संकेत है।

तालिका 1 – वर्ष 2025-26 में नियुक्तियों हेतु संस्तुतियां

पद	पीएसबी	एफआई	पीएसआईसी
अध्यक्ष	-	-	-
सीएमडी	-	-	2
एमडी और सीईओ	3	-	1
एमडी	2	1	1
डीएमडी	-	3	-
ईडी	8	-	6
कुल	13	4	10

सरकारी क्षेत्र के बैंक

इस ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के दो पदों हेतु संस्तुतियां कीं। वर्ष 2025-26 के दौरान केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एमडी और सीईओ तथा विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यपालक निदेशक के आठ पदों के लिए भी संस्तुतियां की गईं।

उक्त पदों में से केनरा बैंक में एमडी और सीईओ के पद हेतु खुले विज्ञापन के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए, जबकि अन्य पदों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यपालकों के पूल में से अपेक्षित

मानदंडों को पूरा करने वाले केवल पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए।

वित्तीय संस्थान

इस ब्यूरो को अधिदेश दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों के विभिन्न पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के नामों की संस्तुति करे। वर्ष के दौरान इस ब्यूरो ने आईआईएफसीएल में एमडी के पद हेतु और आईएफसीआई लि., सिडबी, और नाबार्ड में डीएमडी के पदों हेतु संस्तुतियां कीं। इन पदों के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मंगाए गए। पारस्परिक चर्चा से पहले पात्र अभ्यर्थियों के बारे में योग्यता आकलन की समेकित व्यवस्था के अनुसार योग्यता आकलन किया गया।

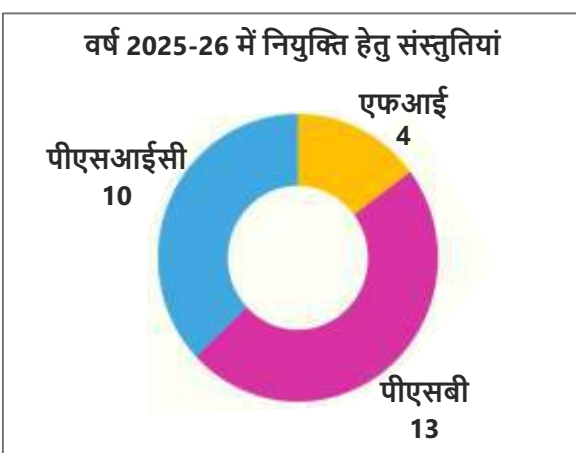
सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां

वर्ष के दौरान इस ब्यूरो द्वारा एलआईसी में सीईओ और एमडी, ओआईसीएल और जीआईसी आरई में सीएमडी, और एलआईसी में एमडी के पदों हेतु संस्तुतियां की गईं। इस ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में कार्यपालक निदेशकों के छह पदों हेतु संस्तुतियां भी की गईं। जीआईसी आरई में सीएमडी के पद को छोड़कर, सभी पद पीएसआईसी

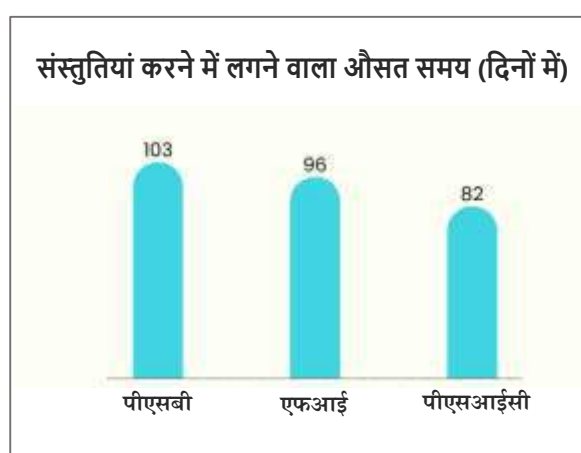
अधिकारियों के पूल से उन अधिकारियों का साक्षात्कार लेकर भरे गए जो आवश्यक मानदंड पूरे करते थे। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जीआईसी आरई में सीएमडी का पद प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए भी खुला है और इसे खुले विज्ञापन के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके भरा गया था।

समय 115 दिन रहा, जबकि भीतरी अभ्यर्थियों के माध्यम से भरी गई रिक्तियों के मामले में 89 दिन लगे।

सभी संस्थानों के लिए संस्तुतियां करने में लिया गया औसत समय (94 दिन) – सरकारी क्षेत्र के बैंकों (103 दिन), वित्तीय संस्थानों (96 दिन) और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (82 दिन) – लिए गए कुल समय का भारित औसत है।



आरेख 2 – क्षेत्र अनुसार संस्तुतियां



खुले विज्ञापनों के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों के मामले में संस्तुतियां करने में लगने वाला औसत

तालिका 2: वर्षवार संस्तुतियां

पद	अवधि	रिक्ति	पात्र अभ्यर्थी	संस्तुत अभ्यर्थी
राष्ट्रीयकृत बैंकों में एनईसी	2023-24	7	-	5
	2024-25	5	-	-
	2025-26	8	-	-
राष्ट्रीयकृत बैंकों में एमडी और सीईओ	2023-24	1	-	1
	2024-25	2	31	2
	2025-26	3	40	3
राष्ट्रीयकृत बैंकों में ईडी	2023-24	13	72	13
	2024-25	4	57	4
	2025-26	8	80	8
एसबीआई में अध्यक्ष	2023-24	-	-	-
	2024-25	1	3	1
	2025-26	-	-	-
एसबीआई में एमडी	2023-24	1	13	1
	2024-25	2	25	2
	2025-26	2	10	2
वित्तीय संस्थानों में अध्यक्ष / एमडी	2023-24	-	-	-
	2024-25	3	41	3
	2025-26	1	6	1
वित्तीय संस्थानों में डीएमडी	2023-24	5	45	5
	2024-25	1	4	1
	2025-26	4	22	3
पीएसआईसी में सीएमडी	2023-24	4	11	4
	2024-25	1	5	1
	2025-26	2	10	2
एलआईसी में सीईओ और एमडी / अध्यक्ष	2023-24	-	-	-
	2024-25	-	-	-
	2025-26	1	4	1
एलआईसी में एमडी	2023-24	2	7	2
	2024-25	2	8	2
	2025-26	2	5	1
पीएसआईसी में जीएमडी/ईडी	2023-24	10	25	9
	2024-25	5	15	5
	2025-26	6	19	6
आईपीपीबी में एमडी और सीईओ	2023-24	1	18	1
	2024-25	-	-	-
	2025-26	-	-	-

कौशल संवर्धन और सशक्तीकरण

निदेशकों हेतु परिवर्धन कार्यक्रम

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थानों/ सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बोर्डों को सशक्त बनाने और इनकी क्षमता बढ़ाने के महत्त्व को स्वीकार करते हुए वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो ने आईबीए और अन्य हिस्सेदारों के सहयोग से निदेशकों हेतु परिवर्धन कार्यक्रम (डीडीपी) को डिजाइन किया और इसे आरंभ किया।

हावार्ड बिजनेस पब्लिशिंग की साझेदारी में मैसर्स इगोन जीहेन्डर प्रा. लि. द्वारा संचालित यह व्यापक कार्यक्रम भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, और बीमा कम्पनियों के निदेशकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।

यह कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ अपना मूल तत्त्व ब्यूरो को दिए गए उस प्रधान अधिदेश से ग्रहण करता है, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थानों / सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों हेतु समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के लिए दिया गया है।

नौ माह के इस कार्यक्रम में वेबिनारों, आमने-सामने परिचर्चा सत्रों, और स्वतः प्रगत ऑनलाइन मॉड्यूलों का मिश्रण शामिल है। सहभागियों को बोर्ड की प्रभावशीलता से संबंधित नवीनतम प्रवृत्तियों पर अभिकेन्द्रित सुसाधित प्रकरण अध्ययनों में भी शामिल किया जाता है। यह कार्यक्रम उद्योग के लीडरों और विषय के विशेषज्ञों से परिचर्चा का अवसर प्रदान करता है जिससे संबंधित विषयों के बारे में गहरी जागरूकता का सृजन होता है।

डीडीपी का सम्यकतापूर्ण दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि निदेशक अपने-अपने संस्थानों को

विकसित हो रहे कारोबारी परिदृश्य के अनुरूप बनाते हैं और नए अवसरों का लाभ उठाते हैं, और इस प्रकार वे अपने विभिन्न हिस्सेदारों के लिए ज्ञान और दिशानिदेश के एक स्रोत के रूप में काम करते हैं। ऐसा करके वे भारतीय वित्तीय संस्थानों के निष्पादन मानकों को वैश्विक स्तर पर लाने में योगदान कर सकते हैं।

डीडीपी के तृतीय बैच का परिसमापन

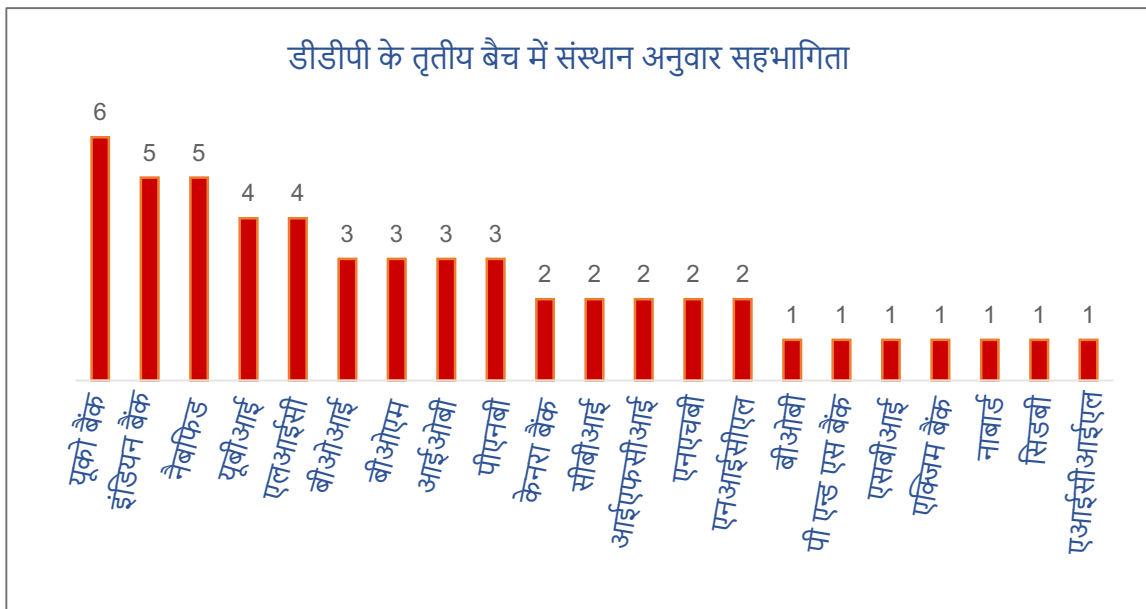
डीडीपी के तृतीय बैच का परिसमापन तीन दिवसीय आवासीय मॉड्यूल के साथ हुआ, जिसका आयोजन 7 से 9 मई 2025 को किया गया था। व्यक्तिगत रूप से संचालित सत्रों में श्री दिनेश खारा (एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष) का प्रमुख संबोधन रहा। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन को वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न उच्च पदधारियों ने संबोधित किया। इनमें श्री भानु प्रताप शर्मा (अध्यक्ष, एफएसआईबी), श्री एम. नागराजु (सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग और सदस्य, एफएसआईबी), और श्री अतुल कुमार गोयल (मुख्य कार्यपालक, आईबीए) शामिल थे।

प्रख्यात वक्ताओं, कॉर्पोरेट अभिशासन के यशस्वियों और उद्योग के अग्रणियों द्वारा अनौपचारिक वार्ताओं, पैनल चर्चाओं, और प्रकरण अध्ययनों जैसे आकर्षक रूपों के माध्यम से विभिन्न सत्रों में मार्गदर्शन किए गए।

विषयों की सम्यक कवरेज, वक्ताओं की गुणवत्ता और कार्यक्रम की सम्पूर्ण संरचना जैसे क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए सहभागियों द्वारा इस कार्यक्रम की सराहना की गई।

डीडीपी के तीन अनुगणों ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के 170 से भी अधिक निदेशकों को लाभान्वित किया और सुविज्ञ निर्णय लेने में भली-भांति

प्रशिक्षित निदेशकों के महत्त्व, अनुपालन को सुनिश्चित करने, और वित्तीय संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण को रेखांकित किया।



डीडीपी के तृतीय बैच के समापन सत्र की एक झलक



लीडरशिप परिवर्धन कार्यक्रम

लीडरशिप परिवर्धन कार्यक्रम (एलडीपी) वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो और आईबीए द्वारा संकलित प्रमुख कार्यक्रम है और यह ज्ञानवान साझेदारों द्वारा संचालित है। एलडीपी का लक्ष्य है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे भविष्यदर्शी प्रवर्तकों का पोषण करने में मदद करना, जो सहक्रियाशील टीमों बना सकते हों और गतिशील प्रतिस्पर्धी परिवेश में ग्राहक-केन्द्रित संस्थाओं का सृजन कर सकें।

एलडीपी का विजन इस ब्यूरो को दिए गए एक अधिदेश से प्रेरित है अर्थात - 'सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के प्रबंधनतंत्र हेतु समुचित प्रशिक्षण और परिवर्धन कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार को सलाह प्रदान करना।'

आरोहण 2025 के बारे में

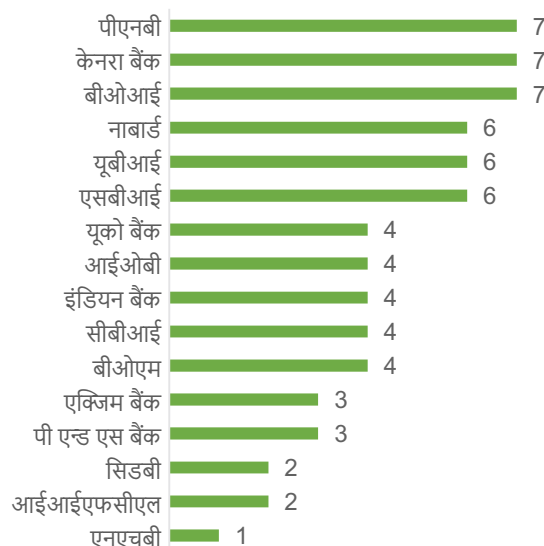
इस कार्यक्रम का षष्ठम बैच ज्ञानवान साझेदार मैसर्स मेकिन्सी द्वारा प्रस्तुत किया गया। आरोहण 2025 का परिसमापन 9 दिसम्बर 2025 को मुख्य अतिथि श्री भानु प्रताप शर्मा (अध्यक्ष, एफएसआईबी) की मौजूदगी में आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ। आरोहण 2025 में सरकारी क्षेत्र के 12 बैंकों और पांच वित्तीय संस्थानों से मुख्य महाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों और उप महाप्रबंधकों के 78 सहभागी आए। एलडीपी में भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम के प्रमुख मॉड्यूलों में अनुभवात्मक मंच, अंतर्निहित मानसिकता को उजागर करने के लिए वन-ऑन-वन कोचिंग सत्र, और नवीनतम जानकारीयों व

उद्योग के रुझानों को शामिल करने वाले ज्ञान अंश शामिल थे। कार्यक्रम में कभी भी, कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल भी शामिल था। तीन अनुभवात्मक मंचों में नेतृत्व कौशल, कार्यात्मक ज्ञान और आध्यात्मिक तल्लीनता पर सत्र शामिल थे।

अगस्त 2025 में अल्पाइन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रिया में आयोजित फोरम-2 में हिस्सेदारों के नेटवर्क के प्रबंधन और विश्वसनीयता के निर्माण की कला, लीडर के रूप में स्वीकार्यता और खुलेपन पर परिचर्चा की गई।

आरोहण 2025 में संस्थान अनुसार सहभागिता



आरोहण 2025 में व्यवसाय परियोजनाएं

व्यवसाय परियोजनाएं इस कार्यक्रम का आंतरिक भाग रही हैं, जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में

अनुभवमूलक मंचों से अध्ययन के अनुप्रयोग का एक अवसर प्रदान करती हैं।

श्री ओम प्रकाश भट (पूर्व अध्यक्ष, एसबीआई), श्री एम. के. जैन (पूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्री गॉटफ्रेड लेब्रान्ड (पूर्व सीईओ, स्विफ्ट, ब्रसेल्स), और श्री अतुल कुमार गोयल (मुख्य कार्यपालक, आईबीए) को शामिल करके गठित व्यवसाय परियोजना समीक्षा समिति द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन से सहभागियों को अत्यधिक लाभ हुआ।

एलडीपी के इस बैच के कार्यकाल के दौरान इन परियोजनाओं की समीक्षा कारोबारी परियोजना समीक्षा समिति द्वारा दो बार की गई, और विभिन्न वर्गों में पारितोषिक भी दिए गए।

चतुर्थ, पंचम और षष्ठम बैचों का सफलतापूर्वक

समापन होने के बाद, मैसर्स बीसीजी की साझेदारी में मैसर्स इगोन जेहेन्डर प्रा. लि. का चयन सप्तम बैच के बाद के बैचों के संचालन हेतु किया जा चुका है।



आरोहण 2025 के तृतीय फोरम की झलकियां



डाटाबेस, आईटी सिस्टम और प्रशासन

अधिकाधिक दक्षता प्राप्त करने की प्रत्याशा में इस ब्यूरो ने अपनी परिचालनात्मक व्यवस्था में बहुविध प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों का एकीकरण किया गया है। इन डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा इसके क्रियाकलापों का समर्थन किया जाता है और साथ ही साइबर-सुरक्षा पर प्रबल फोकस को भी बनाए रखा है। इस ब्यूरो की वर्तमान आईटी अवसंरचना और प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है –

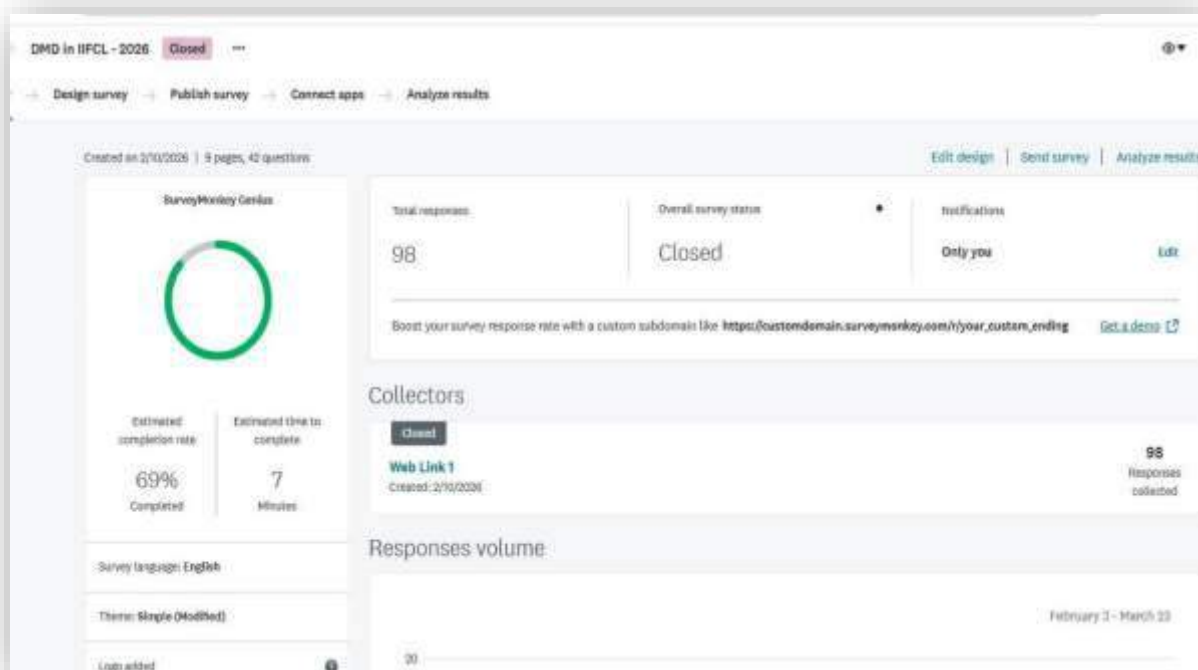
(क) सर्वे मन्की

इस ब्यूरो द्वारा निष्पादित विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करने में सुविधा हेतु अभ्यर्थियों से मिली जानकारी / प्रलेखों का संग्रह करने

और इनका विश्लेषण करने की अपेक्षा होती है। इसलिए इस प्रक्रिया के कुशल संचालन के लिए ब्यूरो अपने सर्वेक्षणों के सृजन, प्रेषण और विश्लेषण के लिए सर्वे मन्की टूल का उपयोग करता है।

(ख) गूगल वर्कस्पेस

इस ब्यूरो द्वारा गूगल वर्कस्पेस का प्रयोग कस्टम ईमेल के साथ fsib.org.in डोमेन पर किया जाता है और इसमें जीमेल, कैलेंडर, ड्राइव, डॉक्स, शीट, इत्यादि जैसे संचयन टूल्स भी शामिल हैं। ब्यूरो अपने आधिकारिक डिस्कॉर्स में गूगल वर्कस्पेस के नौ लाइसेन्सों का उपयोग करता है।



आरेख 3 – सर्वे मन्की – भर्ती हेतु आवेदनों के लिए एक उपाय

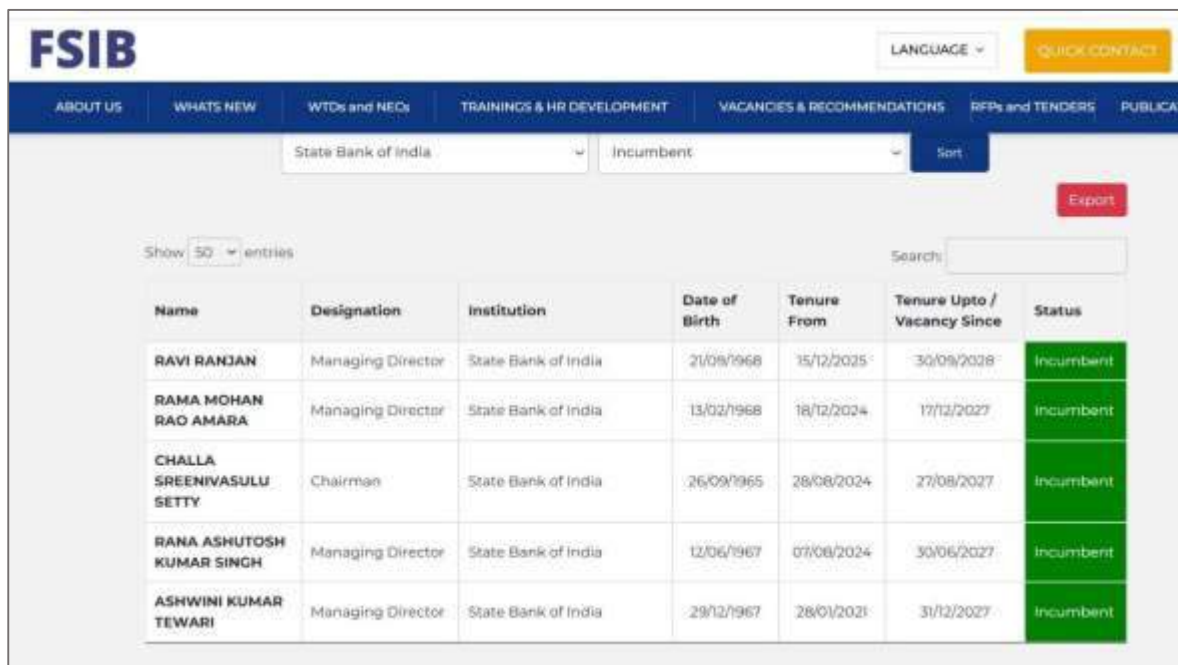
(ग) वीडियो सम्मेलन सुविधा

विभिन्न पदों के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के साथ ब्यूरो अपने साक्षात्कारों का आयोजन या तो भौतिक रूप में करता है या फिर ऑनलाइन वार्तालाप करता है। ऑनलाइन साक्षात्कारों को निर्धारित पद्धति के अनुसार वीसी सुविधा के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए ब्यूरो ने सिसको वेबएक्स हेतु प्रयोक्ता लाइसेन्स लिया है जिससे बैठकों और वार्तालापों के लिए ऑनलाइन मोड में सहायता मिलती है।

(घ) पूर्णकालिक निदेशकों और एनईसी के बारे में डाटाबेस

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के बोर्डों में पूर्णकालिक निदेशकों और एनईसी के बारे में ब्यूरो ऑनलाइन

डाटाबेस का रखरखाव करता है। यह एक वेब एप्लीकेशन है जो कॉन्टेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (सीएमएस) के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। यह वेब एप्लीकेशन एडब्ल्यूएस सर्वर पर होस्ट की जाती है, जो चौबीसों घंटे साइट की सुरक्षा, निगरानी, और बैकअप प्रदान करता है। सीएमएस एक निरापद इंटरफेस के माध्यम से ब्यूरो को डाटाबेस का रखरखाव करने में सक्षम बनाता है। यह डाटाबेस ब्यूरो की वेबसाइट के साथ एकीकृत है और इसमें प्रयोक्ता अपने लिए रिक्त पदों के अलावा पदधारी तथा सेवानिवृत्त बोर्ड सदस्यों, उनके कार्यकाल आदि की स्थितियों के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सकता है। परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्यूरो के सचिवालय द्वारा नियमित रूप से डाटा अद्यतन किया जाता है।



Name	Designation	Institution	Date of Birth	Tenure From	Tenure Upto / Vacancy Since	Status
RAVI RANJAN	Managing Director	State Bank of India	21/08/1968	15/12/2025	30/09/2028	Incumbent
RAMA MOHAN RAO AMARA	Managing Director	State Bank of India	13/02/1968	18/12/2024	17/12/2027	Incumbent
CHALLA SREENIVASULU SETTY	Chairman	State Bank of India	26/09/1965	28/08/2024	27/08/2027	Incumbent
RANA ASHUTOSH KUMAR SINGH	Managing Director	State Bank of India	12/06/1967	07/08/2024	30/06/2027	Incumbent
ASHWINI KUMAR TEWARI	Managing Director	State Bank of India	29/12/1967	28/01/2021	31/12/2027	Incumbent

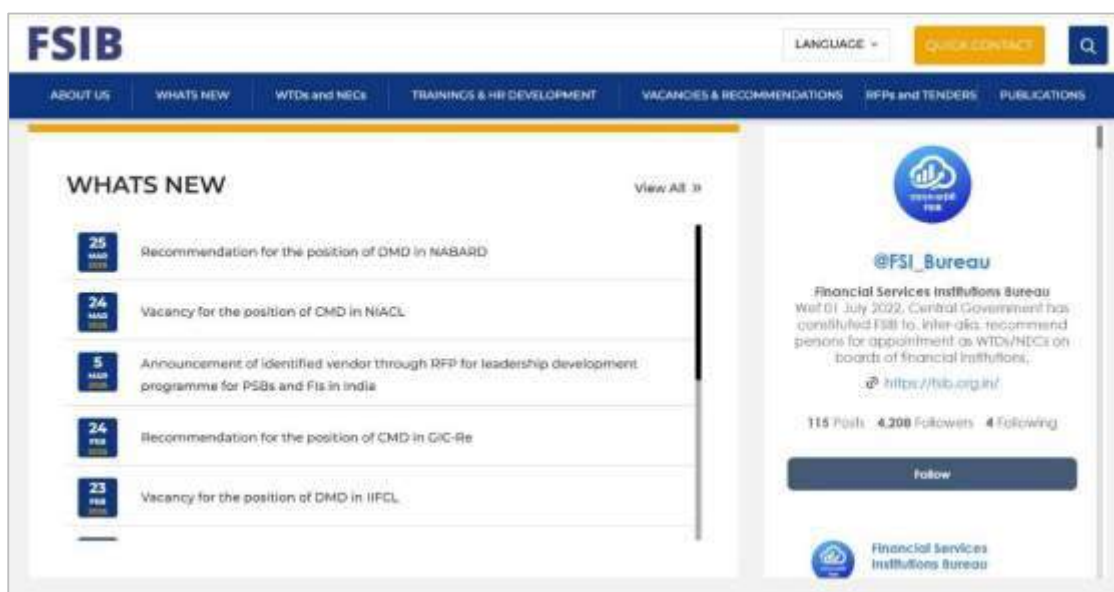
आरेख 4 – बोर्डों के गठन के बारे नवीकृत डाटाबेस को दिखाते हुए स्क्रीनशॉट, जैसा ब्यूरो की वेबसाइट पर प्रकाशित होता है।

(ड) समेकन – ऑनलाइन एचआर डाटाबेस

समेकन का आशय है प्रबंधन और कर्मचारी सेवा एवं ज्ञान विषयक डाटा संकलन और इसके विश्लेषण की प्रणाली। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की समेकित प्रोफाइल एक ही स्थल पर उपलब्ध कराने की परिकल्पना इस एप्लीकेशन में की गई है। इसमें मानव संसाधन के विभिन्न मैट्रिक्स जैसे कि जेन्डर अनुपात, क्रेडिट, आईटी आदि विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता आदि के बारे में बेन्चमार्क और विश्लेषणात्मक रिपोर्टें भी ली जा सकती हैं। इस एप्लीकेशन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के शैक्षणिक विवरण और कैरियर के विवरण भी होस्ट किए जाते हैं। इस पोर्टल पर सुधार की गुंजाइश के बारे में बैंकों से व्यापक फीडबैक लेने के बाद इस एप्लीकेशन की समीक्षा की जा रही है।

(च) ब्यूरो की वेबसाइट

ब्यूरो की वेबसाइट क्लाउड आधारित वेबसाइट डिजाइन, होस्टिंग और सुरक्षा विशेषताओं से युक्त नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह पूरी तरह से वर्डप्रेस पर आधारित कॉन्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत है, जिसकी सहायता से इसका सचिवालय किसी भी बाहरी वेन्डर पर निर्भर रहे बिना तेजी से सामग्री को नवीनतम बना लेता है। यह वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने के लिए सर्वे-मन्की के साथ, ब्यूरो के हैंडल (@FSI_Bureau) से फीड प्रदर्शन हेतु ट्विटर के साथ, और पूर्णकालिक निदेशकों तथा एनईसी संबंधी डाटाबेस के लिए MySQL के साथ भी एकीकृत है, साथ ही फायरवॉल है और गूगल एनालिटिक्स, आदि का भी समावेश है।



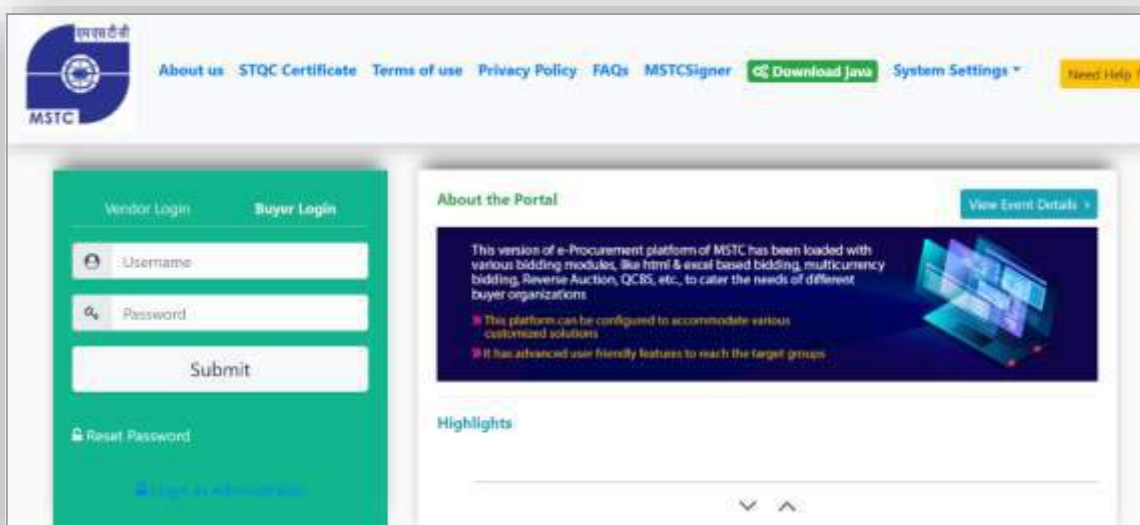
आरेख 5 – एफएसआईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर 'Whats New' खंड की एक झलक

(छ) आधिकारिक ट्विटर हैन्डल

लोगों तक बेहतर पहुंच और जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए सभी अहम सूचनाओं, निविदा नोटिसों, आवेदनों, संस्तुतियों आदि को ब्यूरो के आधिकारिक 'X' (ट्विटर) (@FSI_Bureau) हैन्डल पर भी प्रकाशित किया जाता है।

(ज) ई-निविदा पोर्टल

ब्यूरो को मैसर्स एमएसटीसी लि. की ई-प्रोक्वेरमेन्ट पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है। यह पोर्टल पूर्णतया सुरक्षित ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली प्रदान करता है। विभिन्न सेवाओं के अधिक्रय हेतु सभी निविदाओं और कोटेशनों को इसी पोर्टल के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए इस ब्यूरो ने अपने सचिवालय के प्रयोग हेतु ई-मुद्रा के डिजिटल प्रमाणपत्रों का प्रयोग किया जाता है।



आरेख 6 – एफएसआईबी द्वारा ई-निविदाओं के लिए प्रयुक्त निविदा पोर्टल – मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड

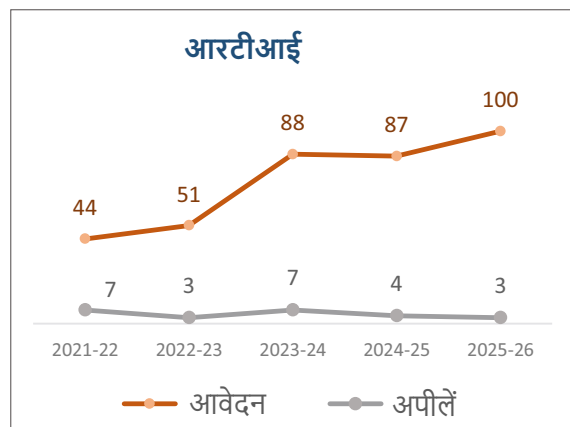
(ज) सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2025 में दी गई परिभाषा के अनुसार वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो एक लोक प्राधिकरण है। वर्ष के दौरान ब्यूरो द्वारा प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों का सारांश निम्नानुसार है –

तालिका 3 – आरटीआई आवेदन

वर्ष	आवेदन	अपील
2025-26	100	3
2024-25	87	4
2023-24	88	7
2022-23	51	3
2021-22	44	7

लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत पारदर्शिता संपरीक्षा प्रकटीकरण का संचालन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे द्वारा किया गया।



वर्ष के दौरान इस ब्यूरो को आरटीआई के 100 आवेदन और तीन प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं। आवेदकों से 95 आवेदन सीधे ही प्राप्त हुए, जबकि पांच आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों द्वारा हस्तांतरित किए गए। इन 100 आवेदनों में से 62 का हस्तांतरण अन्य लोक प्राधिकरणों को किया गया, दो आवेदन आवेदकों को लौटा दिए गए क्योंकि मांगी गई जानकारी का संबंध राज्य सरकारों से था और 36 आवेदनों और तीन प्रथम अपीलों को निर्धारित समय के भीतर निपटाया गया।

तृतीय पक्ष द्वारा की गई संपरीक्षा रिपोर्ट को ब्यूरो की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा चुका है। इस संपरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर सीआईसी परामर्श को भी इस ब्यूरो आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रकटीकरण को ने स्वतः प्रेरणा से अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है जिससे आरटीआई आवेदकों को सहायता मिले।

प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां

इस ब्यूरो की प्राप्तियां वह धनराशियां हैं, जो उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों, जो वर्तमान में इस ब्यूरो के दायित्व-क्षेत्र में हैं, से मिलती हैं। ब्यूरो द्वारा किए गए व्ययों (किये जा चुके और प्रत्याशित) को संस्थान के वर्ग-अनुसार अर्थात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के बीच उनकी अपनी-अपनी रिक्तियों के लिए दी गई सेवा के समानुपात में विभाजित कर दिया जाता है। विद्यमान निदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बीमा कंपनियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और वित्तीय संस्थानों के लिए नाबार्ड नोडल संस्थान के रूप में हैं।

इस ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों का लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक में इसके खाते के माध्यम से किया जाता है। नोडल संस्थानों से प्रत्याशित योगदान वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्राप्त हो जाते हैं। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर अधिशेष निधियों को संबंधित नोडल संस्थानों को वापस कर दिया जाता है।

भुगतान

प्रमुख भुगतान एफएसआईबी के लिए मुम्बई में परिसर लेने के लिए लीज के किराए और कार्मिकों पर आने वाली लागतों से संबद्ध हैं। ये भुगतान ब्यूरो के लिए आवर्ती व्यय हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों के समाकलन और इतिवृत्त के सत्यापन हेतु बाहरी एचआर एजेन्सी की हायरिंग पर व्यय किए जाते हैं। इस ब्यूरो की अपनी स्थायी आस्तियां नहीं हैं क्योंकि अधिकांश फिक्सचर, फर्नीचर और कंप्यूटर हार्डवेयर आदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिये जाते हैं। हार्डवेयर की गौण वस्तुओं को राजस्व व्यय के रूप में मान लिया गया है।

लेखांकन प्रणाली

स्वशासी निकाय के रूप में इस ब्यूरो की अपनी लेखा प्रणाली है। ब्यूरो लेखांकन अवधि की अवधारणा को अपनाता है और अपनी प्राप्तियों और भुगतानों को संचयी आधार पर श्रेणीबद्ध करता है।

वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो
31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि हेतु व्यय और प्राप्तियों का विवरण

व्यय		प्राप्तियाँ			
विवरण	धनराशि (₹.)	धनराशि (₹.) 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि हेतु	विवरण	धनराशि (₹.)	धनराशि (₹.) 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि हेतु
संस्थानों हेतु वास्तविक व्यय के अनुपात के आधार पर भुगतान नाबार्ड भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय स्टेट बैंक	32,47,585 64,95,171 84,79,224 1,82,21,980		गत वर्ष (2024-25) से संस्थानों को देय नाबार्ड भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय स्टेट बैंक	32,47,585 64,95,171 84,79,224 1,82,21,980	
विकासन लागत बोर्डिंग और लॉजिंग विधिक परिव्यय बाह्य एवम् एलेक्सी पर लागत लीडरशिप सेवर्द्धन संबंधी लागत लीज संबंधी लागत विविध लागत व्यक्तिगत लागत मुद्रण, डाक, स्टेशनरी और उपभोग्य वस्तुएं सदस्यों के लिए सिटिंग फीस पीएसआई विशेषज्ञ सदस्य वित्तीय संस्थान विशेषज्ञ सदस्य पीएसबी विशेषज्ञ सदस्य		66,35,513 2,20,707 1,20,750 77,27,820 - 78,46,410 3,07,745 3,03,84,968 2,69,591	प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ (प्रत्याशित रिक्तियों पर आधारित अनुपात) नाबार्ड भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय स्टेट बैंक	61,40,000 3,37,70,000 3,68,40,000	1,40,65,875 2,81,31,750 3,28,20,375 7,50,18,000
साफ्टवेयर और वेबसाइट लागत यात्रा और वाहन भत्ते लेखापरीक्षा व्यय परोक्ष व्यय	17,50,000 7,00,000 25,50,000	28,33,740 3,47,451 1,04,600 44,97,279 - 1,62,30,600 4,25,312 2,52,67,482 2,87,595			
जीएसटी पर दंडात्मक ब्याज व्यय की तुलना में अग्रिम प्राप्तियों का आधिक्य/कमी		9,50,000 5,50,000 26,50,000 41,50,000			
भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय स्टेट बैंक	(30,36,853) 1,08,27,868 70,15,229 1,48,06,244	15,29,662 7,37,642 1,18,000 2,66,657 1,82,21,980			
कुल	7,67,50,000	7,50,18,000	कुल		7,67,50,000
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार कृते डीएम के एस एड्स कम्पनी चार्टर्ड लेखाकार एफ.आर.पुनः 116886W सीए. मालविका लोकेश्वर, साझेदार युडीआईएन : 26108628CVFM1112140 स्थान : मुम्बई दिनांक : 9 जून 2026	ह/- शिशिर कुमार मिश्र ब्यूरो के सचिव और महाप्रबन्धक स्थान : मुम्बई दिनांक : 09-02-2026	ह/- प्रदीप कौर गेवाल सहायक महाप्रबंधक स्थान : मुम्बई दिनांक : 09-02-2026			

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सचिव

वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो

अभिमत

1. हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो (एफएसआईबी) की प्राप्तियों और भुगतानों (विवरण) के विवरण की लेखा परीक्षा की है। इस विवरण को वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो के प्रबंधन वर्ग द्वारा तैयार किया गया ताकि वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो द्वारा किए गए भुगतानों और तदनुसूची प्राप्तियों की सत्य और उचित प्रस्तुति की जा सके।
2. हमारे अभिमत से 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक बोर्ड ब्यूरो की प्राप्तियों और भुगतानों के बारे में यह विवरण सत्य और उचित प्रस्तुति करता है।

अभिमत हेतु आधार

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा को आइसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर संचालित किया। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के विवरण खंड के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के दायित्वों में किया गया है। आइसीएआई द्वारा जारी नैतिकता संहिता का अनुसरण करते हुए हम वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो से स्वतंत्र हैं और हमने इस नैतिकता संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को भी पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा के जो भी साक्ष्य हमने प्राप्त किए वे हमारे अभिमत हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

4. वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो के भुगतानों और उनके समानुरूप प्राप्तियों का सत्य और उचित प्रकटीकरण करने के लिए इस विवरण को तैयार करने और उचित प्रस्तुति का दायित्व वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो के प्रबंधन तंत्र का है। इस दायित्व में पर्याप्त अभिलेखों के रखरखाव और विवरण को तैयार करने और उचित प्रस्तुति हेतु सुसंबद्ध आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जिससे यह विवरणी धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण हो सकने वाले किसी भी तात्त्विक अपविवरण से मुक्त है।

विवरण की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक का दायित्व

5. हमारा उद्देश्य है कि इस बारे में समुचित भरोसा प्राप्त करें कि समग्र रूप से यह विवरण सभी प्रकार के वास्तविक अपविवरणों से मुक्त है, चाहे यह अपविवरण धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, और फिर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करें जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। पर्याप्त सुनिश्चितता एक प्रकार से उच्च स्तरीय सुनिश्चितता होती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में जब भी कोई वास्तविक अपविवरण हुआ है तो हमेशा ही कोई वास्तविक अपविवरण पकड़ में आएगा। किसी भी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण अपविवरण हो सकते हैं, और इन्हें वास्तविक माना जाता है, यदि अलग-अलग अथवा सम्यक तौर पर इस विवरण के आधार पर प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों पर पर्याप्त रूप से इनका प्रभाव पड़ना प्रत्याशित हो।

6. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के तौर पर हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयवाद बरकरार रहता है। हम वक्तव्य में वास्तविक अपविवरण के जोखिम को भी अभिनिर्धारित करते हैं और उसका आकलन करते हैं, चाहे वह अपविवरण धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण हो, इन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा का प्रतिसादात्मक डिजाइन और निष्पादन करते हैं, और अपने अभिमत के आधार स्वरूप पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी से पैदा होने वाले वास्तविक अपविवरण को नहीं पकड़ पाने का जोखिम त्रुटियों के कारण होने वाले अपविवरण से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, अपप्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड करना निहित होता है।

7. इस लेखापरीक्षा हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की ताकि परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखापरीक्षा पद्धति डिजाइन की जा सके।

8. संलग्न विवरणों के वितरण अथवा उपयोग पर प्रतिबंध – इसके साथ दिया जा रहा विवरण केवल वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो की जानकारी के लिए ही तैयार किया गया है और इसलिए यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए उचित नहीं रहेगा। यह रिपोर्ट केवल उपरोल्लिखित प्रयोजन से जारी की गई है और तदनुसार बिना हमारी लिखित सहमति के इसका किसी अन्य प्रयोजन या किसी अन्य पार्टी को इसका संदर्भ अथवा विवरण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बिना हमारी लिखित सहमति के यदि किसी अन्य को यह रिपोर्ट दिखाई जाती है या उसके हाथ पड़ जाती है तो किसी अन्य प्रयोजन या अन्य व्यक्ति की वजह से हम किसी दायित्व को स्वीकार अथवा अंगीकार नहीं करेंगे।

कृते डीएमकेएच एन्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 116886W

ह. /-
सीए. मालविका लोकेश्वर
साझेदार
सदस्यता संख्या – 108628
यूडीआइएन : 26108628CVFMIU2140
स्थान : मुम्बई
दिनांक : 09-06-2026

CONTENTS

Financial Services Institutions Bureau Composition	3
Overview	5
Establishment And Functions	7
Recommendations For Appointment	9
Skill Enhancement And Empowerment.....	12
• Directors Development Programme	12
• Leadership Development Programme	14
Databases, IT Systems And Administrative Works	16
Receipts And Payments Account	21
Independent Auditor's Report.....	23

LIST OF ABBREVIATIONS

ACC	Appointments Committee of the Cabinet	IOB	Indian Overseas Bank
AICIL	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
BOB	Bank of Baroda	LDP	Leadership Development Programme
BOI	Bank of India	LIC	Life Insurance Corporation of India
BOM	Bank of Maharashtra	MD	Managing Director
CBI	Central Bank of India	MD & CEO	Managing Director and Chief Executive Officer
CEO	Chief Executive Officer	NABARD	National Bank for Agriculture and Rural Development
CGM	Chief General Manager	NaBFID	National Bank for Financing Infrastructure and Development
CIC	Central Information Commission	NEC	Non-Executive Chairman
CMD	Chairman-cum-Managing Director	NHB	National Housing Bank
DDP	Directors Development Programme	NICL	National Insurance Company Limited
DFS	Department of Financial Services	OBC	Oriental Bank of Commerce
DGM	Deputy General Manager	OICL	Oriental Insurance Co. Ltd.
DMD	Deputy Managing Director	P&S Bank	Punjab and Sind Bank
DPE	Department of Public Enterprises	PNB	Punjab National Bank
ED	Executive Director	PSIC	Public Sector Insurance Company
FI	Financial Institution	PSB	Public Sector Bank
FSIB	Financial Services Institutions Bureau	RBI	Reserve Bank of India
GIC Re	General Insurance Corporation of India	RTI	Right to Information
GM	General Manager	SBI	State Bank of India
GMD	General Manager & Director	SIDBI	Small Industries Development Bank of India
IBA	Indian Banks' Association	UBI	Union Bank of India
IIFCL	India Infrastructure Finance Company Ltd.	WTD	Whole Time Director
IFCI	Industrial Finance Corporation of India	WTM	Whole Time Member

COMPOSITION OF THE FSIB DURING THE FY 2025-26#

		
Shri M. Nagaraju	Shri Bhanu Pratap Sharma Chairman	Shri K. Moses Chalai
Secretary, DFS Ex-Officio Member (PSB/FI/PSIC)		Secretary, DPE [^] Ex-Officio Member (PSB/FI/PSIC)
		
Shri Shirish Chandra Murmu		Shri Ajay Seth
Deputy Governor, RBI [@] Ex-Officio Member (PSB/FI)		Chairman, IRDAI* Ex-Officio Member (PSIC)
		
Shri Animesh Chauhan		Smt Usha Sangwan
Former MD & CEO, OBC Expert Member (PSB/FI)		Former MD, LIC Expert Member (PSIC)
		
Shri Shailendra Bhandari		Shri A.V. Girija Kumar
Former MD & CEO, ING Vysya Bank Expert Member (PSB/FI)		Former CMD, OICL Expert Member (PSIC)
		
Shri Deepak Singhal		Shri Sujay Banarji
Former ED, RBI Expert Member (PSB/FI)		Former WTM, IRDAI Expert Member (PSIC)

[^] Since April 22, 2025

[@] Since October 09, 2025

^{*} Since September 01, 2025

#The terms of the Chairperson and Part-time Members of the FSIB ended on June 30, 2026

PRINCIPAL OFFICERS OF THE SECRETARIAT

Shri Shishir Kumar Mishra (Till July 31, 2026)
Shri Ashish Kumar Verma (wef August 01, 2026)

Secretary & General Manager

Ms. Pradeep Kaur Grewal

Assistant General Manager

Shri Gajenthira Siva S #

Assistant General Manager

Shri Prateek Jain

Manager

Shri Navneet Mehrol

Manager

Shri Devansh Rawat \$
Shri KV Sai Krishna &

Assistant Manager

Shri Adithya M

Assistant Manager

All the above officers are from the Reserve Bank of India.

Since April 20, 2026 \$ Till April 02, 2026 & Since May 04, 2026

OVERVIEW

Financial Services Institutions Bureau ('the Bureau') is an autonomous body of Government of India for developing and implementing appropriate methodologies for making recommendations for appointments, extension in tenure and termination of WTDs in public sector financial institutions. The Bureau is mandated to advise the Government on the desired structure at Board/senior management level, performance appraisal systems thereof and formulation and enforcement of a code of conduct and ethics for managerial personnel in the specified institutions.

Recommendations for Appointment

During the year 2025-26, the Bureau met on 20 occasions to make recommendations for 27 positions across PSBs, PSICs and Fis, interacting with 196 candidates in the process. Of the 27 recommendations made during the year, 13 recommendations were made for PSBs, four recommendations for FIs and 10 recommendations for various positions in PSICs.

Apart from making recommendation for appointments, the Bureau also made recommendations for extension of tenure of MD of IIFCL, DMD of EXIM Bank, MD & CEOs and EDs of PSBs during the year.

The meetings and interactions of the Bureau took place both in online as well as physical mode. Online meetings were held through the CISCO WebEx platform and physical meetings were held in New Delhi.

Skill Enhancement and Empowerment

The Bureau is mandated, inter-alia, to evolve suitable training and development programmes for management personnel in specified institutions. The Bureau, in association with external knowledge partners, has curated two programmes, viz. the Directors Development Programme (DDP) and the Leadership Development Programme (LDP).

DDP is designed to enhance the capabilities of Boards of PSBs/FIs/PSICs. The third batch of DDP, which concluded in May 2025, was delivered by M/s Egon Zehnder along with Harvard Business Publishing, witnessed participation from 53 directors across PSBs/FIs/PSICs. Participants include Whole Time, Independent, Shareholder, and Nominee Directors.

LDP is designed to transform high-potential executives across Public Sector Banks and Financial Institutions into future leaders. M/s McKinsey has been the knowledge partner for the programme for Batches IV, V and VI of LDP. The sixth batch of LDP, known

as “Aarohan 2025”, comprised of 78 CGMs, GMs and DGMs from 12 PSBs and 5 FIs, and it culminated in December 2025. M/s Egon Zehnder in partnership with M/s BCG have been selected as knowledge partners to carry forward LDP from Batch VII onwards.

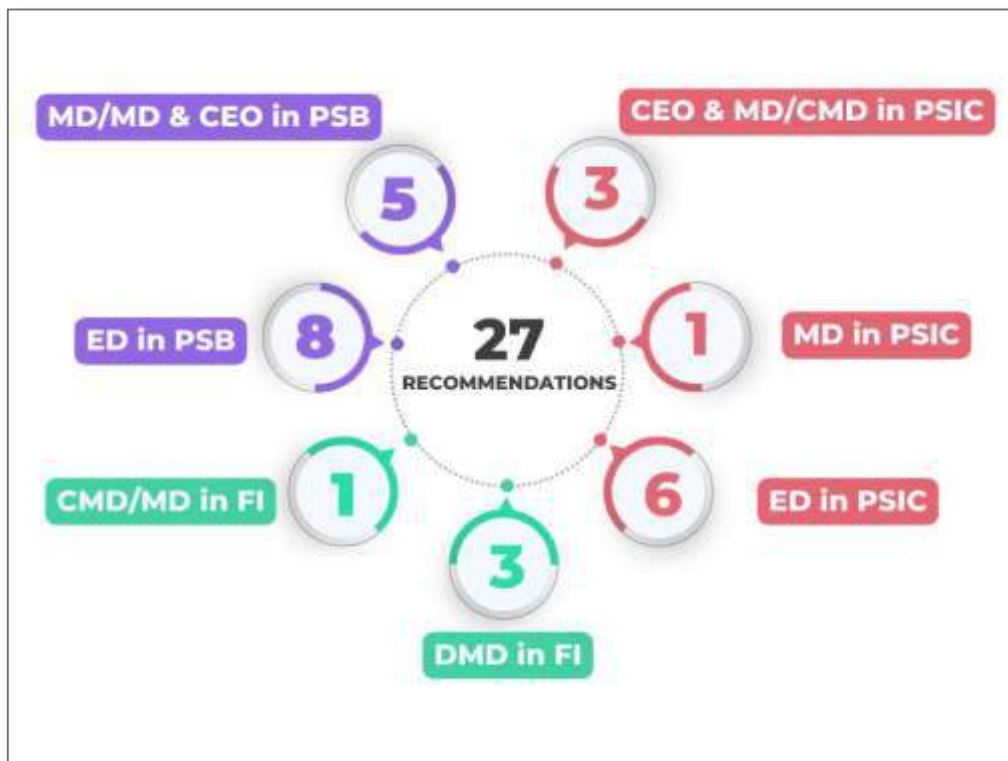


Figure 1: Recommendations in 2025-26

ESTABLISHMENT AND FUNCTIONS

The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) was set up under Government of India Resolution F.No./14/1/2022-BO-I dated July 01, 2022 for the purpose of, inter alia, recommending persons for appointment as whole-time directors and non-executive chairpersons on the Boards of mandated institutions and for advising on certain other matters relating to personnel management in these institutions.

The Bureau conducts the selection process for all WTD positions in PSBs, FIs, and PSICs in accordance with guidelines approved by the ACC. These guidelines include Eligibility Criteria (viz. age, experience etc.), Term of Office, Procedure for Selection etc.

During the year, the ACC approved revised consolidated guidelines for appointment of WTDs in the mandated institutions. In addition to revision in eligibility criteria, some of the major changes in the revised guidelines are provided below:

- Certain WTD positions such as MD in SBI (one position), MD & CEO in Nationalised Banks, ED in large banks (one position), MD in LIC (one position) and CMD in PSICs, which were previously filled by internal candidates, are now open to private sector candidates as well.
- The consideration of APAR marks has been removed for the positions of Chairman in SBI, MD in SBI, MD & CEO in PSBs (other than large banks), CEO & MD in LIC, MD in LIC and CMD in PSICs.
- The weightage for APAR marks has been reduced from 50% to 30% for the positions of ED in PSICs and ED (positions earmarked for internal candidates only) in Nationalised Banks.
- Penalty clauses have been added, in which candidates with a history of two or more major penalties will not be considered for the WTD positions.

Mandated Institutions

Public Sector Banks



Financial Institutions



Public Sector Insurance Companies



RECOMMENDATIONS FOR APPOINTMENT

During the year, the Bureau made recommendations for 27 positions in various financial services institutions. The ratio of candidates with whom the Bureau interacted per vacancy was 7.2, indicating a healthy pool of candidates for the positions.

Table 1: Recommendations for appointment in 2025-26

Position	PSBs	FIs	PSICs
<i>Chairman</i>	-	-	-
<i>CMD</i>	-	-	2
<i>MD & CEO</i>	3	-	1
<i>MD</i>	2	1	1
<i>DMD</i>	-	3	-
<i>ED</i>	8	-	6
<i>Total</i>	13	4	10

Public Sector Banks

The Bureau made recommendations for two positions of Managing Director in SBI. Recommendations for MD & CEO in Canara Bank, Union Bank of India and Central Bank of India and eight Executive Director positions in various PSBs were also made during 2025-26.

Among the above positions, for the position of MD & CEO in Canara Bank, applications were sought from eligible candidates through open advertisement, whereas for

the other positions only the eligible candidates from the pool of PSB executives meeting the requisite criteria were interviewed.

Financial Institutions

The Bureau is mandated to recommend names of suitable candidates for various WTD positions in Public Sector FIs. During the year, the Bureau made recommendations for the position of MD in IIFCL, and for the positions of DMD in IFCI Ltd., SIDBI and NABARD. Applications were sought through open advertisement for these positions. Competency assessment, as per the comprehensive competency assessment framework, was carried out for eligible candidates before the interactions.

Public Sector Insurance Companies

During the year, the Bureau made recommendations for the positions of CEO & MD in LIC, CMD in OICL and GIC Re, and for MD in LIC. The Bureau also made recommendations for six positions of Executive Directors in PSICs. All these positions, except CMD in GIC Re, were filled by interviewing the eligible candidates from

the pool of PSIC executives meeting the requisite criteria. As per the revised guidelines, the position of CMD in GIC Re is open to private candidates as well and was filled by inviting applications from eligible candidates through open advertisement.

the vacancy was filled from internal candidates.

The average time for making the recommendations across institutions (94 days) is the weighted average of the time



Figure 2: Sector- wise recommendations



The average time taken for making the recommendations in case of vacancies which had to be filled through open advertisement was 115 days, whereas it was 89 days when

taken for recommending positions in PSBs (103 days), FIs (96 days) & PSICs (82 days).

Table 2: Year- wise recommendations

<i>Position</i>	<i>Period</i>	<i>Vacancy</i>	<i>Eligible candidates</i>	<i>Recommended candidates</i>
NEC in Nationalised Banks	2023-24	7	-	5
	2024-25	5	-	-
	2025-26	8	-	-
MD & CEO in Nationalised Banks	2023-24	1	-	1
	2024-25	2	31	2
	2025-26	3	40	3
ED in Nationalised Banks	2023-24	13	72	13
	2024-25	4	57	4
	2025-26	8	80	8
Chairman in SBI	2023-24	-	-	-
	2024-25	1	3	1
	2025-26	-	-	-
MD in SBI	2023-24	1	13	1
	2024-25	2	25	2
	2025-26	2	10	2
Chairman / MD in FIs	2023-24	-	-	-
	2024-25	3	41	3
	2025-26	1	6	1
DMD in FIs	2023-24	5	45	5
	2024-25	1	4	1
	2025-26	4	22	3
CMD in PSICs	2023-24	4	11	4
	2024-25	1	5	1
	2025-26	2	10	2
CEO & MD/Chairman in LIC	2023-24	-	-	-
	2024-25	-	-	-
	2025-26	1	4	1
MD in LIC	2023-24	2	7	2
	2024-25	2	8	2
	2025-26	2	5	1
GMD/ED in PSICs	2023-24	10	25	9
	2024-25	5	15	5
	2025-26	6	19	6
MD & CEO in IPPB	2023-24	1	18	1
	2024-25	-	-	-
	2025-26	-	-	-

SKILL ENHANCEMENT AND EMPOWERMENT

Directors Development Programme

Recognizing the significance of empowering and enhancing the capabilities of Boards of PSBs/FIs/PSICs, the Financial Services Institutions Bureau, in collaboration with IBA and other stakeholders, introduced the Directors Development Programme (DDP).

Delivered by M/s Egon Zehnder in partnership with Harvard Business Publishing, DDP is a comprehensive programme specifically tailored for directors of PSBs/FIs/PSICs in India.

The programme, inter-alia, derives its roots from the enshrined mandate of the Bureau on the development of suitable training programmes for PSBs/FIs/PSICs.

The nine-month programme features a blend of webinars, in-person interactive sessions, and self-paced online modules. Participants also engage in facilitated case studies focused on the latest trends on board effectiveness. The programme offers opportunity for interaction with industry leaders and subject matter experts to create deeper awareness of relevant issues.

The holistic approach of DDP ensures that the directors adapt their organizations to the evolving business landscape and capitalize on new opportunities, thereby serving as a

source of wisdom and guidance for various stakeholders. By doing so, they can contribute to raising the performance standards of Indian financial institutions on the global stage.

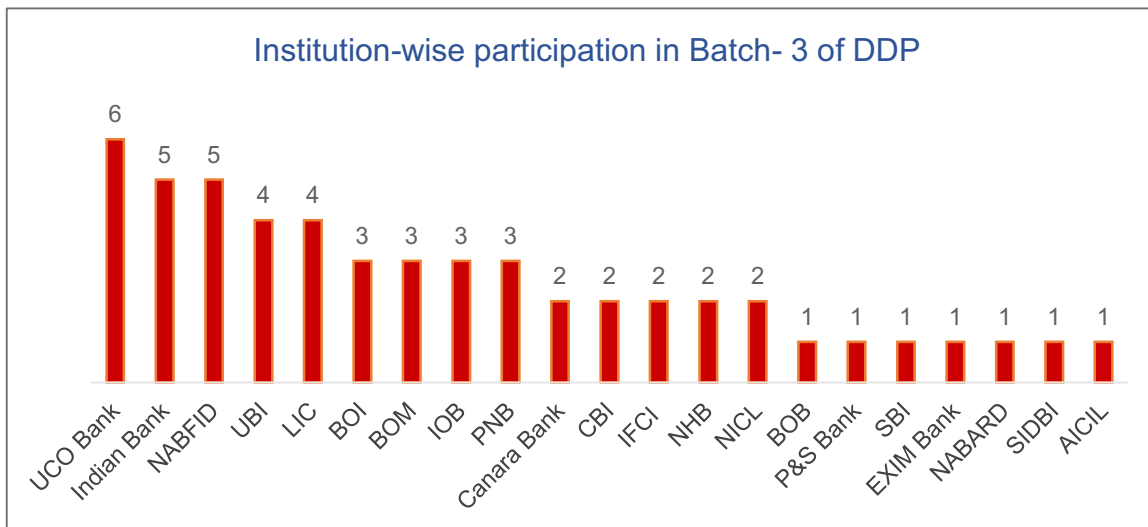
Culmination of 3rd Batch of DDP

The third batch of DDP concluded with a three-day residential module, which was held from May 7-9, 2025. The engaging in-person sessions comprised of a keynote address by Shri Dinesh Khara (Former Chairman, SBI). Several dignitaries from the Financial Sector addressed the participants on the final day of the programme. This included Shri Bhanu Pratap Sharma (Chairman, FSIB), Shri M. Nagaraju (Secretary, DFS and Member, FSIB) and Shri Atul Kumar Goel (Chief Executive, IBA).

Eminent speakers, corporate governance luminaries and industry stalwarts guided various sessions through engaging formats like fireside chats, panel discussions, and case studies.

The participants appreciated the programme, particularly highlighting areas such as thorough coverage of topics, quality of speakers and overall structure of the programme.

The three cohorts of DDP benefitted over 170 directors of PSBs/FIs/PSICs, underscoring the importance of well-trained directors in making informed decisions, ensuring compliance, and effectively governing financial institutions.



Glimpse from valediction of 3rd Batch of DDP





Leadership Development Programme

The Leadership Development Programme (LDP) is a flagship programme curated by FSIB and IBA, and delivered by a knowledge partner. LDP aims to help PSBs and FIs in fostering forward-thinking leaders who can build synergetic teams, and create customer-centric organizations in a dynamic competitive environment.

LDP derives its vision from one of the mandates to the Bureau: “to advise the Government on evolving suitable training and development programmes for management personnel in PSBs, FIs and PSICs”.

About Aarohan 2025

The sixth batch of the programme “Aarohan 2025” was delivered by M/s McKinsey as the knowledge partner. Aarohan 2025 culminated with a valediction ceremony held on December 09, 2025 in the presence of the chief guest Shri Bhanu Pratap Sharma (Chairman, FSIB).

A cohort of 78 CGMs, GMs and DGMs from 12 Public Sector Banks and five Financial Institutions participated in Aarohan 2025. SBI participated for the first time in LDP.

The key modules of the programme included Experiential Forums, one-on-one Coaching Sessions to uncover underlying mindsets,

and Knowledge Nuggets covering the latest learnings and industry trends. The programme also included an online learning module to provide anytime, anywhere learning access. Three experiential forums covered sessions on leadership skills, functional knowledge, and spiritual immersion.

The Forum 2 held at Alpine University, Austria in August 2025, touched upon the art of managing stakeholder networks and building reliability, acceptance and openness as a leader.



Business Projects in Aarohan 2025

Business Projects have been an integral part of the programme, providing an opportunity

to apply learnings from the experiential forums in real-life situations.

The participants benefitted immensely from guidance provided by the Business Project Review Committee comprising Shri Om Prakash Bhatt (Former Chairman, SBI), Shri M.K. Jain (Former Deputy Governor, RBI), Shri Gottfried Leibbrandt (Former CEO, SWIFT, Brussels), and Shri Atul Kumar Goel (Chief Executive, IBA).

The projects were reviewed two times during the tenure of this batch of LDP by the Business Project Review Committee, and were awarded across various categories.

After successful completion of batches IV, V and VI, M/s Egon Zehnder in partnership with M/s BCG has been selected to deliver the programme from Batch VII onwards.



Glimpses from Forum 3 of Aarohan 2025



DATABASES, IT SYSTEMS AND ADMINISTRATION

In pursuit of greater efficiency, the Bureau has integrated multiple technology-enabled systems into its operational framework. These digital platforms support its activities while maintaining a strong focus on cybersecurity. The Bureau's present IT infrastructure and technological capabilities are outlined below.

(a) Survey Monkey

Various activities performed by the Bureau such as facilitating selection of WTDs require collection and analysis of

information/ documents from the candidates who apply for WTD positions. Therefore, for efficient conduct of the process, the Bureau utilizes the Survey Monkey tool to create, send and analyse such surveys.

(b) Google Workspace

The Bureau uses google workspace with custom email with domain fsib.org.in and also includes collaboration tools like Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets etc. The Bureau utilizes nine google workspace licenses in its official discourse.

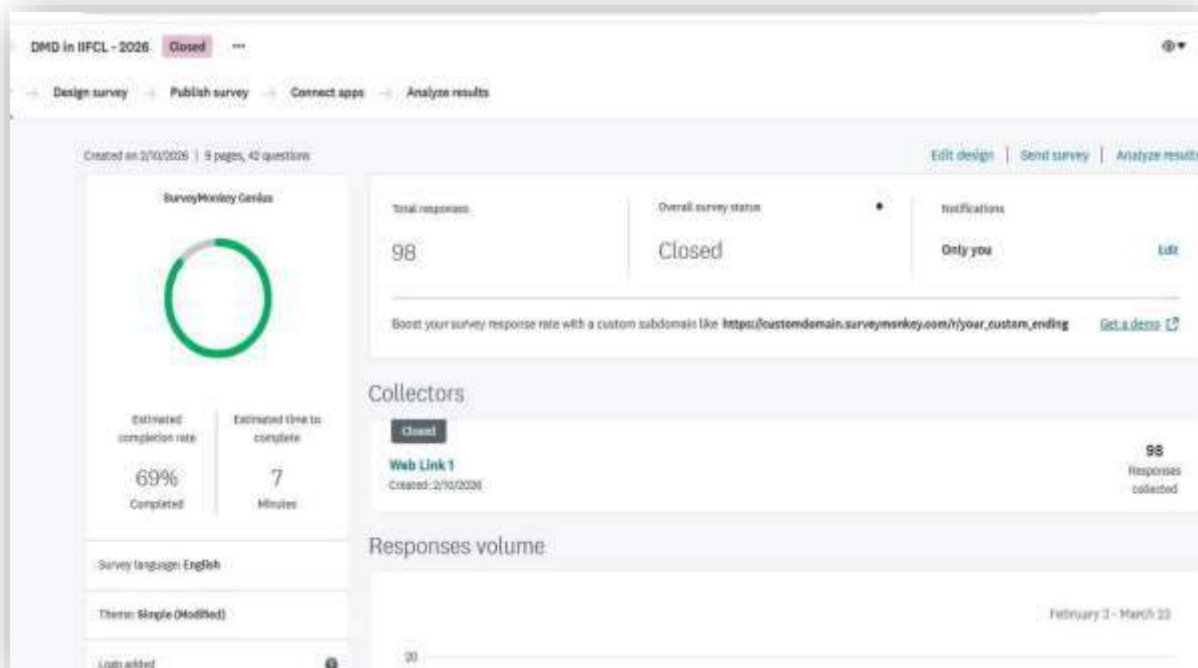


Figure 3: Survey Monkey - A tool to source recruitment applications

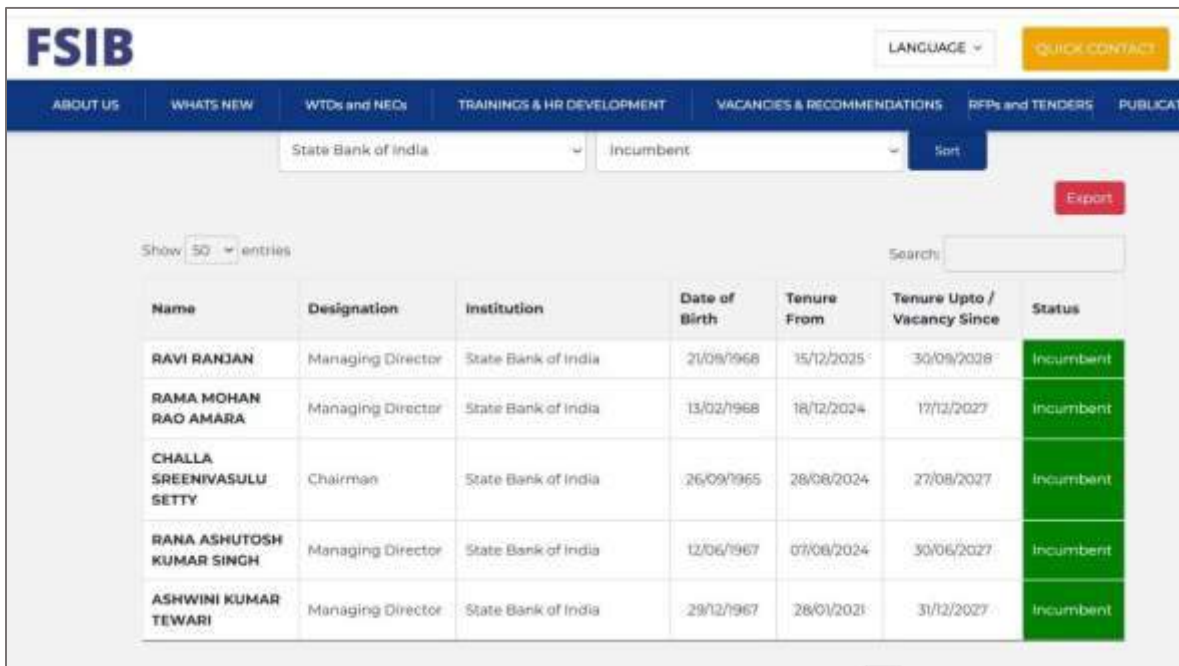
(c) Video Conferencing Facility

The Bureau conducts interviews either through physical or online interaction with candidates appearing for various positions. Online interviews are held through VC facility as per the laid down procedures. For the purpose, the Bureau has acquired user licenses for CISCO WebEx to support the online mode for meetings and interactions.

(d) Database on WTDs and NECs

The Bureau maintains an online database of WTDs and NECs on the boards of PSBs, PSIs and FIs. This is a web application fully

integrated with a Content Management System (CMS). This web application is hosted on AWS server that provides round the clock site security, monitoring and backup. The CMS enables the Bureau to maintain the database through a secure interface. The database is integrated with the website of the Bureau and allows the user to generate reports showing the incumbent and the retired Board Members, their tenures etc. apart from the vacant positions. The Secretariat regularly updates the data to ensure accuracy.



Name	Designation	Institution	Date of Birth	Tenure From	Tenure Upto / Vacancy Since	Status
RAVI RANJAN	Managing Director	State Bank of India	21/08/1968	15/12/2025	30/09/2028	Incumbent
RAMA MOHAN RAO AMARA	Managing Director	State Bank of India	13/02/1968	18/12/2024	17/12/2027	Incumbent
CHALLA SREENIVASULU SETTY	Chairman	State Bank of India	26/09/1965	28/08/2024	27/08/2027	Incumbent
RANA ASHUTOSH KUMAR SINGH	Managing Director	State Bank of India	12/06/1967	07/08/2024	30/06/2027	Incumbent
ASHWINI KUMAR TEWARI	Managing Director	State Bank of India	29/12/1967	28/01/2021	31/12/2027	Incumbent

Figure 4: Screenshot highlighting updated database on composition of Boards as published on Bureau's website

(e) SAMEKAN - Online HR database

SAMEKAN stands for System to Assimilate data on Management and Employee service & Knowledge and its Analysis. This application envisages to provide comprehensive profile of all senior officers of PSBs and specified FIs at a single location. It also provides benchmarks and analytical reports on various human resource metrics such as gender ratio, expertise in specific areas like credit, IT etc. The application hosts data related to education details and career details of senior officers of PSBs and FIs. The application is under review after taking extensive feedbacks from banks on scope of improvements in the portal.

(f) Website of the Bureau

The website of the Bureau is based on the state-of-the-art technologies with cloud-based website design, hosting and security features. It is fully integrated with a Word Press based Content Management System that allows the Secretariat to quickly update the content without depending on any external vendor. The website is also integrated with Survey Monkey for accepting online applications, with Twitter for display of feeds from the Bureau's handle (@FSI_Bureau), with a MySQL database on WTDs and NECs, with a firewall, with Google analytics etc.

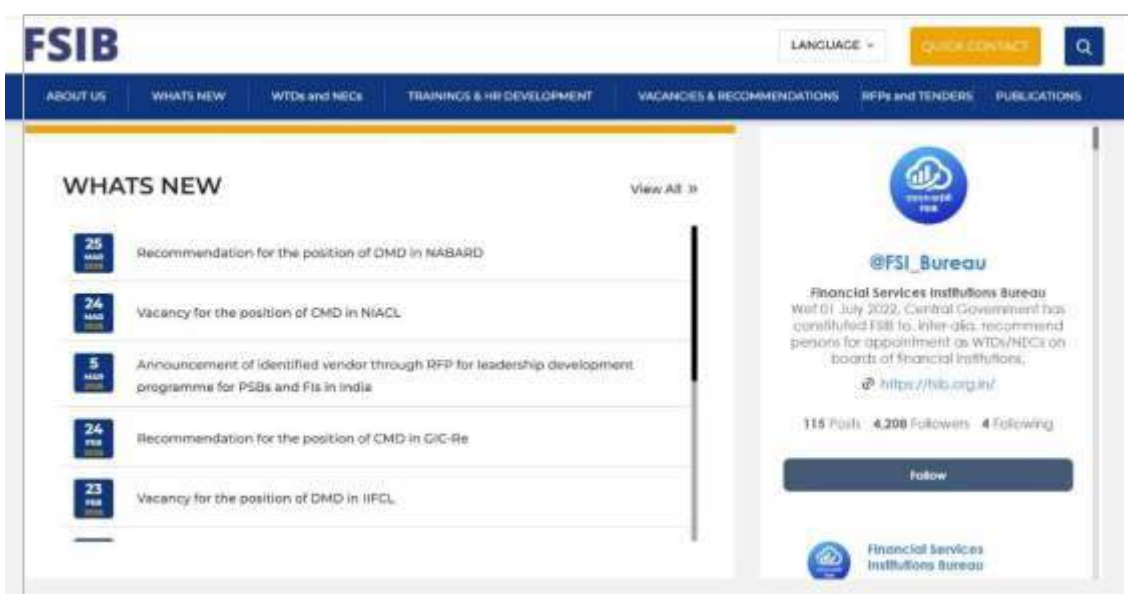


Figure 5: Glimpse of "Whats New" Section of the official website of FSIB

(g) Official Twitter Handle

All key notifications, tender notices, applications, recommendations etc. are also published on the Bureau's official 'X' (twitter) handle (@FSI_Bureau) for quick and better public outreach and wider information dissemination.

(h) E-Tendering Portal

The Bureau is on-boarded on EProcurement portal of the M/s MSTC Ltd. The portal provides for the fully secure online e-tendering system. For procurement of various services, tenders and quotations are being floated through this portal. For the purpose, the Bureau secretariat uses digital certificates from E- mudhra.

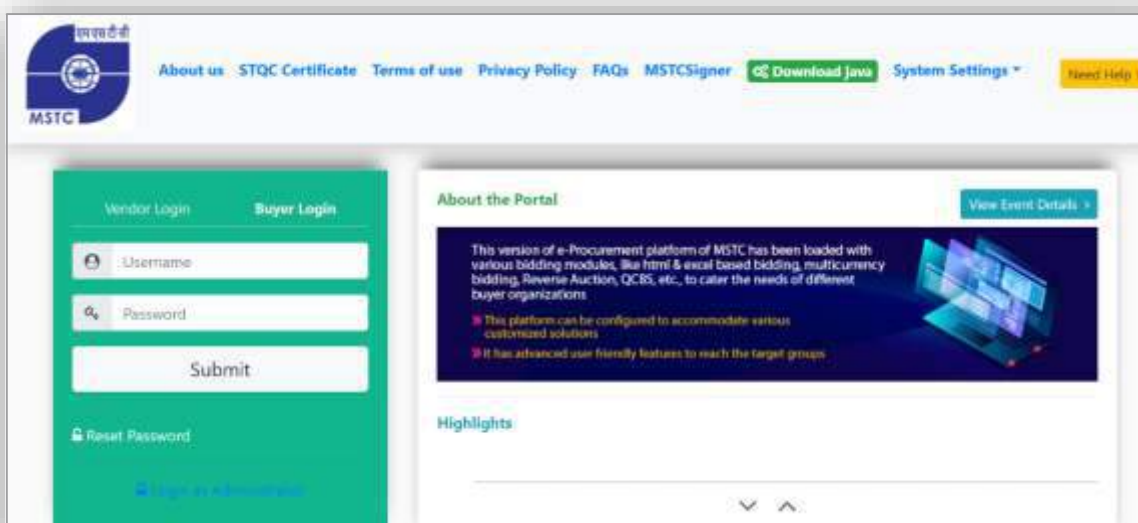


Figure 6: E-Tendering Portal – M/s MSTC Ltd used by FSIB for e-tendering

(h) Right to Information

The FSIB is a public authority as defined in the Right to Information Act, 2005. The summary of RTI applications and Appeals received by the Bureau during the year is given below.

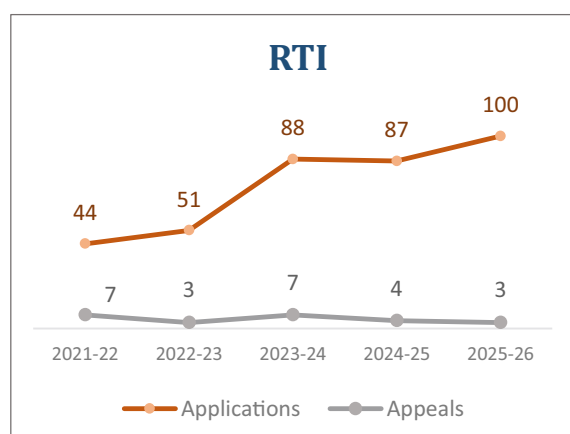
Table 3- RTI applications

Year	Applications	Appeals
2025-26	100	3
2024-25	87	4
2023-24	88	7
2022-23	51	3
2021-22	44	7

During the year, the Bureau received a total of 100 RTI applications and three first appeals. 95 applications were received directly from the applicants while five were transferred by other Public Authorities. Of these 100 applications, 62 were transferred to other Public Authorities, two were returned to applicants as the information sought were pertaining to State Governments and 36 applications and three

first appeals were disposed of within the stipulated time.

Transparency Audit of Disclosures u/s 4 of the RTI Act by the Public Authorities was conducted by College of Agricultural Banking, RBI, Pune for the financial year 2024-25.



The third party audit report has been published on the Bureau's website. As per the CIC advisory based on the audit report, the Bureau has also updated the suo-moto disclosure u/s 4 of the RTI Act on its website to help RTI applicants.

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

Receipts

The Receipts of the Bureau are amounts received from various PSBs, PSICs and FIs that are currently within the remit of the Bureau. The expenses (both incurred and projected) are divided among the institution categories i.e. PSBs, PSICs and FIs, in proportion of the respective vacancies that were serviced by the Bureau. As per the extant directions, the nodal institution is SBI for PSBs, LIC for PSICs and NABARD for FIs.

The receipts and payments of the Bureau are routed through an account maintained at the Reserve Bank of India. The anticipated contributions from the nodal institutions are received at the beginning of the financial year. The excess funds, based on the audited financials, are refunded to the respective nodal institutions.

Payments

The major payments are related to lease rentals towards hiring of premises for FSIB at Mumbai and personnel costs. These constitute the recurring expenses of the Bureau. Further, expenses are incurred for hiring an external HR agency for assessment and background verification of candidates. There are no fixed assets of the Bureau as majority of the fixtures, furniture and computer hardware etc. are provided by RBI. Minor items of hardware are considered as revenue expenses.

Accounting System

The Bureau, as an autonomous body, has its own system of accounts. The Bureau maintains an accounting period concept and aligns its receipts and payments on accrual basis.

Receipts and Payments Statement for the year ended March 31, 2026

Financial Services Institutions Bureau
Statement of Expenditure and Receipts for the period ended 31st March 2026

EXPENDITURE			RECEIPTS		
PARTICULARS	AMOUNT (RS) For the period ended March 31, 2026	AMOUNT (RS) For the year ended March 31, 2025	PARTICULARS	AMOUNT (RS) For the period ended March 31, 2026	AMOUNT (RS) For the year ended March 31, 2025
Payment in ratio based on actual expenditure to these institutions			Payable to institutions from previous year (2024-25)		
NABARD	32,47,585		NABARD	32,47,585	
LIC	64,95,171		LIC	64,95,171	
SBI	84,79,224		SBI	84,79,224	
	1,82,21,980			1,82,21,980	
Advertisement Costs		66,35,513	Reimbursement Received (Ratio based on Anticipated vacancies)		
Boarding & Lodging		2,20,707	NABARD	28,33,740	1,40,65,875
Legal Expense		1,20,750	LIC	3,47,451	2,83,31,750
External HR Agencies Costs		77,27,820	SBI	44,97,279	3,28,20,375
Leadership Development Related Cost		-			
Lease Related Expenses		78,46,410			
Miscellaneous Costs		3,07,745			
Personnel Costs		3,03,84,958			
Printing, Postage, Stationery and Consumables		2,69,591			
Sitting Fees to Members		-			
PSI Expert Member	17,50,000	9,50,000			
PSI Expert Member	7,00,000	5,50,000			
PSI Expert Member	25,50,000	26,50,000			
Software and Website Costs		50,00,000			
Travel & Conveyance		13,59,143			
Audit Charges		19,43,310			
		1,29,800			
Indirect Expenses					
Penal interest on GST		-			
		2,66,657			
Excess/Deficit of Receipts over Expenditure received in advance					
NABARD		1,82,21,980			
LIC	(30,36,853)				
SBI	1,08,27,868				
	70,15,229				
	1,48,06,244				
Total	7,67,50,000	7,50,18,000	Total	7,67,50,000	7,50,18,000

As per our report of even date

FOR D M K & CO.

Chartered Accountants

FRN: 116886W

mbkeshwar

CA. Malavika Ishwar

Partner

Membership No.: 106628

UDIN: 26108428CVFMJ112340

Place: Mumbai

Date: 09th June, 2026

FOR FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS BUREAU

Shashir Kumar Mishra

Secretary to the Bureau and General Manager

Place: Mumbai

Date: 09.06.2026

Pradeep Kaur Grewal

Pradeep Kaur Grewal

Assistant General Manager

Place: Mumbai

Date: 09.06.2026

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT



DMKH & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Independent Auditor's Report

The Secretary
Financial Services Institutions Bureau

Opinion

1. We have audited the accompanying statement of Expenditure and Receipts (the statement) of M/s Financial Services Institutions Bureau (FSIB) for the period ended March 31, 2026. It has been prepared by management of Financial Services Institutions Bureau to give the True and Fair view of the Expenditure and corresponding Receipts of the Financial Services Institutions Bureau.

2. In our opinion, the statement presents a true and fair view of the Expenditure and Receipts of Financial Services Institutions Bureau for the period ended March 31, 2026.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the statement section of our report. We are independent of the Financial Services Institutions Bureau in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with Code of Ethics. We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibility of Management for the Statement

4. Management of Financial Services Institutions Bureau is responsible for the preparation and fair presentation of this statement to give the True and Fair view of the expenditure and corresponding receipts of the Financial Services Institutions Bureau. This responsibility also includes maintenance of adequate records and for the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of the statement that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Statement

5. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the statement as a whole is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these statement.



803-804, Ashok Heights, NICCO Circle, Near Bhuta School, Old Nagardas Lane, Gundavalli, Andheri (East), Mumbai - 400 069.
Tel : 022-26824800 / 4900 | Email : contact@dmkhca.in | www.dmkhca.in

Head Office: Mumbai, Branch Office: Pune | Ahmedabad | Gandhinagar | Surat | Vadodara | Ballari | Delhi | Udaipur

6. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also identify and assess the risks of material misstatement of the statement, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

7. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

8. Restriction on distribution or use the accompanying statement have been prepared solely for information and use of Financial Services Institutions Bureau only and accordingly may not be suitable for any other purpose. This report is issued solely for the aforementioned purpose and accordingly, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our written consent. Further, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

FOR D M K H & CO.
Chartered Accountants
FRN: 116886W

CA. Malavika Lokeshwar



CA. Malavika Lokeshwar
Partner

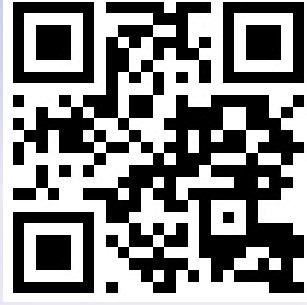
Membership No.: 108628

UDIN: 26108628CVFMIU2140

Place: Mumbai

Date: 09.06.2026

For latest updates



<https://fsib.org.in/>



https://x.com/FSI_Bureau

वित्तीय सेवा संस्था ब्यूरो

Financial Services Institutions Bureau

4th Floor, Byculla Office of Reserve Bank of India, Opposite Mumbai Central Railway Station, Mumbai, India - 400 008

+91 22 2302 8454

secretariat@fsib.org.in

<https://fsib.org.in>